



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 930]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2007/श्रावण 5, 1929

No. 930]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2007/SRAVANA 5, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2007

(आय-कर)

का.आ. 1281(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (3) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ख) और धारा 139घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आय की विवरणी का इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतीकरण स्कीम, 2004 को, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना का.आ. 1073(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2004 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जो अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या जिनको किए जाने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन स्कीम का संक्षिप्त नाम आय की विवरणी का इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतिकरण स्कीम, 2007 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं - इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) “अंकीय चिन्हक” से प्रमाणक प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी प्रमाणक प्राधिकारी द्वारा जारी अंकीय चिन्हक अभिप्रेत है ;

(घ) “पात्र व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे स्थाई लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है और जो आय की विवरणी या प्ररूप आईटीआर-1, प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3, प्ररूप आईटीआर-4, प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6 या प्ररूप आईटीआर-8 में अनुषंगी फायदों की विवरणी देने के लिए अपेक्षित है ;

स्पष्टीकरण - कोई फर्म या कोई कंपनी, जो आय-कर नियम 1962 के नियम 12 के उपनियम (3) के उपबंधों कि अधीन, अंकीय चिन्हक हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक रूप में कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए या इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी के डाटा पारेषित करने के लिए और उसके पश्चात् प्ररूप आईटीआर-5 में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, वह इस स्कीम के प्रयोजन के लिए पात्र व्यक्ति भी है ।

(ङ) “ई-विवरणी” से इस स्कीम के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी का इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित डाटा अभिप्रेत है जिसके समर्थन में आय का सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप आईटीआर-5 फाइल किया गया है ;

(च) “ई-विवरणी प्रशासक” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो आय-कर आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जिसे इस स्कीम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अभिहित किया गया है ;

(छ) “ई-विवरणी मध्यवर्ती” से इस स्कीम के अधीन ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) “प्ररूप” से आय-कर नियम, 1962 की परिशिष्ट-2 में यथा उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(झ) “रजिस्ट्रार” से इस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) “नियम” से आय-कर नियम, 1962 में अंतर्विष्ट नियम अभिप्रेत है ;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।

3. ई-विवरणी का फाइल किया जाना - (1) कोई पात्र व्यक्ति, जो आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (3) के परंतुक के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई अन्य पात्र व्यक्ति है, किसी निर्धारण वर्ष 2007-08 या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अपनी ऐसी आय की विवरणी को जिसको वह अधिनियम की धारा 139 या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) या धारा 148 की उपधारा (1) या धारा 153क के अधीन देने के लिए अपेक्षित है या अनुषंगी फायदों की ऐसी विवरणी को जिसको वह अधिनियम की धारा 115 बघ की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन देने के लिए अपेक्षित है, अपने विकल्प पर किसी ऐसे ई-विवरणी मध्यवर्ती को दे सकेगा जो ऐसी विवरणी के डाटा को अंकित करेगा और उसे नियत तारीख को या उससे पूर्व ई-विवरणी प्रशासक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित सर्वर को इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित करेगा ।

(2) पात्र व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी को, ई-विवरणी मध्यवर्ती द्वारा प्राप्त इलैक्ट्रॉनिक डाटा के लिए अनंतिम रसीद को जारी किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर, सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप आईटीआई-5 देगा और वह तारीख जिसको ऐसी रसीद जारी की गई है, विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी।

(3) जहां प्ररूप आईटीआई-5, उपपैरा (2) में विहित समय के भीतर नहीं दिया गया है वहां प्ररूप आईटीआई-5 को दिए जाने की तारीख, विवरणी को फाइल करने की तारीख समझी जाएगी।

4. आय की पुनरीक्षित विवरणी - यदि पैरा (3) में यथावर्णित किसी पात्र व्यक्ति ने इस स्कीम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी या अनुषंगी फायदों की विवरणी दे दी है तो वह इस स्कीम के अधीन उस निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) के अधीन आय या अधिनियम की धारा 115बघ की उपधारा (4) के अधीन अनुषंगी फायदों की पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा।

5. ई-विवरणी मध्यवर्ती की अर्हताएं - (1) ई-विवरणी मध्यवर्ती के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात् :-

(क) उसको, अधिनियम की धारा 2 के खंड (36क) में यथापरिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई अन्य कंपनी जिसमें जनता, अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) के अर्थान्तर्गत पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, होनी चाहिए ; या

(ख) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या अधिवक्ताओं की कोई फर्म जिसको स्थाई लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या कोई अधिवक्ता जिसको कोई स्थाई लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है ; या

(घ) कोई सरकारी विभाग का कोई आहरण या संवितरक अधिकारी।

(2) ई-मध्यवर्ती के पास प्रमाणक प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रमाणक प्राधिकारियों में से किसी से, कम से कम श्रेणी-2 का अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(3) ई-मध्यवर्ती के पास, वह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती की सूचना की गोपनीयता उचित तौर पर सुरक्षित है, ई-विवरणी प्रशासक के समाधानप्रद रूप में सुरक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए।

(4) ई-मध्यवर्ती के पास ई-विवरणियों के लिए जो उसके द्वारा फाइल की जाएंगी, ऐसे आवश्यक आर्किवल, रिट्रिवल और सुरक्षा नीति होनी चाहिए, जो ई-विवरणी प्रशासक द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं।

(5) ई-मध्यवर्ती या उसका मुख्य अधिकारी किसी वृत्तिक अवचार, कपट, गबन या किसी दांडिक अपराध के लिए, यथास्थिति, किसी न्यायालय द्वारा या किसी वृत्तिक निकाय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो।

6. ई-विवरणी मध्यवर्ती को प्राधिकृत किया जाना - (1) ई-मध्यवर्ती के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित व्यक्ति रजिस्ट्रार को ऐसी आवेदन फीस के साथ आवेदन करेगा जो ई-विवरणी प्रशासक द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाए।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार यह सत्यापित करेगा कि आवेदन पूर्ण है और आवश्यक दस्तावेजों द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित है।

(3) किसी कमी की दशा में उन कमियों को ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर दूर करने के लिए आवेदक को उसकी संसूचना दी जाएगी।

(4) ऐसे आवेदनों पर, जो पैरा 5 में विनिर्दिष्ट अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं, आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(5) विधिमान्य आवेदन की दशा में रजिस्ट्रार आवेदक के अध्यक्ष की सम्यक जांच कराएगा।

(6) रजिस्ट्रार आवेदन और सम्यक अध्यक्ष रिपोर्ट, ऑन लाइन ई-विवरणी प्रशासक को पारेषित करेगा और उसके बाद ई-विवरणी प्रशासक नियुक्ति आदेश के साथ ई-विवरणी मध्यवर्ती पहचानपत्र संख्यांक (इआरआईआईएन) और ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए पासवर्ड जारी कर सकेगा।

(7) ई-मध्यवर्ती की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और उसे दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(8) रजिस्ट्रार अपने कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, मताधिकारियों आदि सहित ऐसी किसी सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा जो इस स्कीम के कार्यान्वयन के अनुक्रम के दौरान उनके कब्जे में आती है और ऐसी किसी सूचना को, ई-विवरणी प्रशासक की अनुमति के सिवाय किसी को नहीं देगा।

7. किसी ई-विवरणी मध्यवर्ती कि पूर्वतर स्कीम के अधीन प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय - जहां कोई व्यक्ति, आय की विवरणी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण स्कीम, 2004, के अधीन ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में नियुक्त किया गया है, वहां उसके द्वारा प्रतिभूति निक्षेप, ई-प्रशासक द्वारा विनिश्चित किए गए समय के भीतर, ई-विवरणी प्रशासक द्वारा उसको प्रतिदाय होगा।

8. पात्र व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - ऐसा कोई पात्र व्यक्ति जो इस स्कीम के अधीन अपनी आय की विवरणी देने का विकल्प चुनता है -

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी आय की विवरणी या अनुषंगी फायदे इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं ;

(ii) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अपनी ई-विवरणी देने के प्रयोजन के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु किसी एक ई-विवरणी मध्यवर्ती से संपर्क करेगा और अपनी सहमति देगा।

9. ई-विवरणी मध्यवर्ती द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - (1) ई-विवरणी मध्यवर्ती, यथास्थिति, पात्र व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित आय की पेपर विवरणी प्राप्त करेगा या पात्र व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आय की विवरणी तैयार करेगा।

(2) मध्यवर्ती स्थाई लेखा संख्यांक के विधिमान्यकरण के पश्चात् आय की पूरी विवरणी को, अपनी ई-विवरणी मध्यवर्ती पहचान संख्यांक (इआरआईआईएन) का उपयोग करते हुए ई-विवरणी प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में अपलोड करेगा।

(3) आवश्यक विधिमान्यकरणों के पश्चात् अपलोड की गई विवरणियों को स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक स्वीकार की गई ई-विवरणी के संबंध में उस प्रणाली द्वारा सम्यक् रूप से भरा गया एक प्ररूप आईटीआर-5 अनंतिम रसीद के रूप में तैयार किया जाएगा जिसे मध्यवर्ती को पारेषित किया जाएगा।

(4) मध्यवर्ती संबद्ध पात्र व्यक्ति को यदि उसके द्वारा प्ररूप आईटीआर-5 आय-कर विभाग को देने के लिए संग्रहीत किया गया है तो प्ररूप आईटीआर-5 की अभिस्वीकृति रसीद प्रदान करेगा।

(5) अनंतिम रसीद जारी किए जाने की तारीख आय की विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी यदि प्ररूप आईटीआर-5 निर्धारण अधिकारी को अनंतिम रसीद जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर फाइल कर दी गई है। यदि प्ररूप आईटीआर-5 डाटा अपलोड करने की तारीख से पंद्रह दिन के पश्चात् फाइल की जाती है तो प्ररूप आईटीआर-5 फाइल करने की तारीख आय की विवरणी फाइल करने की तारीख होगी।

10. ई-विवरणी पर कार्यवाही - (1) ई-विवरणी पर पूर्विकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

(2) निर्धारिती को शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो, निर्धारण अधिकारी द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में भारतीय रिजर्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं का उपयोग करते हुए जमा कर दी जाएगी या सीधे निर्धारिती को भेज दी जाएगी।

11. ई-मध्यवर्ती के कृत्य और दायित्व - ई-विवरणी मध्यवर्ती,-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारिती इस स्कीम कि अधीन पात्र व्यक्ति है ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारिती ने सही और विधिमान्य स्थाई लेखा संख्यांक उद्धृत किया है ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर और स्रोत से काटे गए कर की विशिष्टियां संलग्न दस्तावेजों के अनुसार हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि आय की पेपर विवरणी निर्धारिती द्वारा उचित रूप से फाइल की गई है और उसके द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गई है तथा आय की विवरणी के साथ फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित संलग्नक संलग्न हैं ;

(ङ) आय की विवरणी को लिप्यांतर करते समय और उसके पारेषण के दौरान डाटा प्रविष्टि की परिशुद्धता को सुनिश्चित करेगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि आय की विवरणी का इलेक्ट्रॉनिक भाग आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व पारेषित कर दिया जाता है ;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि पेपर विवरणी संबद्ध निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी के पास फाइल कर दी गई है ;

(ज) फाइल की विवरणी कि इलेक्ट्रानिक डाटा को और उसके माध्यम से फाइल की गई विवरणियों के संबंध में जारी अनंतिम रसीदों से संबंधित सूचना को सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिधारित करेगा ;

(झ) निर्धारिती को उसके द्वारा पेश की गई ई-विवरणी की पेपर प्रति और ई-विवरणी मध्यवर्ती द्वारा निर्धारण अधिकारी को फाइल की गई पेपर विवरणी की अभिस्वीकृति रसीद देगा ;

(ञ) उस सूचना की गोपनीयता कायम रखेगा जो इस स्कीम के कार्यान्वयन के अनुक्रम के दौरान उसके कब्जे में आती है और ऐसी किसी सूचना को, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय, किसी को प्रकट नहीं करेगा ;

(ट) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मचारी, अभिकर्ता, मताधिकारी आदि इस स्कीम के उपबंधों का पालन करते हैं ;

(ठ) रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके द्वारा फाइल किए गए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में किसी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को तत्परता से सूचना देगा ;

(ड) इस स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए ई-विवरणी प्रशासक द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा ।

12. ई-विवरणी प्रशासक - (1) ई-विवरणी प्रशासक डाटा के सुरक्षित ग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, फार्मेट और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा स्कीम के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी होगा ।

(2) ई-विवरणी प्रशासक ई-विवरणी मध्यवर्तियों द्वारा स्कीम की तकनीकी अपेक्षाओं के पालन को सुनिश्चित करेगा ।

(3) ई-विवरणी प्रशासक इस स्कीम के उचित और सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए समुचित सुरक्षा, आर्किवल और रिट्रीवल नीतियां विकसित और उनको कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

[अधिसूचना सं. 210/2007/फा. सं. 142/16/2007-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1281(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1B) of Sections 139 and 139D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rule (3) of rule 12 of the Income-tax Rules, 1962 and in supersession of the Electronic Furnishing of Return of Income Scheme, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) under the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes vide S.O. 1073(E), dated the 30th September, 2004, except as respects things done, or omitted to be done, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following scheme, namely :—

1. Short title and commencement.-

- (1) This scheme shall be called the Electronic Furnishing of Return of Income Scheme, 2007.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In this scheme, unless the context otherwise requires —

- (a) "Act" means the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (b) "Board" means Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Board of Revenues Act, 1963 (54 of 1963);
- (c) "digital signature" means a digital signature issued by any Certifying Authority authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying Authorities.
- (d) "eligible person" means a person who has been allotted a permanent account number and who is required to furnish return of income or return of fringe benefits in Form ITR-

1, Form ITR-2, Form ITR-3, Form ITR-4, Form ITR-5, Form ITR-6 or Form ITR-8;
Explanation.— A firm or a company which, under the provisions of sub-rule (3) of Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962, is required to furnish the return electronically under digital signature or transmit the data of the return electronically and thereafter to submit the verification of the return in Form ITR-V is also an eligible person for the purposes of this Scheme;

- (e) "e-Return" means electronically transmitted data of return furnished under this scheme, supported by a duly verified Form ITR-V;
- (f) "e-Return Administrator" means an officer, not below the rank of the Commissioner of Income-tax, designated by the Board for the purpose of administration of this scheme;
- (g) "e-Return Intermediary" means a person authorised to be an e-Return intermediary under this scheme;
- (h) "Form" means the form as set out in Appendix-II of the Income-tax Rules, 1962;
- (i) "Registrar" means a person appointed by the Board to act as a Registrar under this scheme;
- (j) "rule" means the rules contained in the Income-tax Rules, 1962;
- (k) words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Filing of e>Returns.- (1) An eligible person being a company or a firm referred to in clause (a) of proviso to sub-rule (3) of rule 12 of the Income-tax Rules, 1962 or any other eligible person may, at his option, furnish his return of income which he is required to furnish under section 139 or clause (i) of sub-section (1) of section 142 or sub-section (1) of section 148 or section 153A of the Act or return of fringe benefits which he is required to furnish under sub-section (1) or sub-section (2) of section 115WD of the Act for assessment year 2007-08 or any subsequent assessment year, to an e-Return Intermediary who shall digitise the data of such return and transmit the same electronically to a server designated for this purpose by the e-Return Administrator, on or before the due date.

(2) The eligible person shall submit the duly verified Form ITR-V to the Assessing Officer not later than fifteen days from the issue of the provisional receipt for the electronic

data received by the e-Return Administrator and the date on which such receipt is issued shall be deemed to be the date of filing the return.

(3) Where Form ITR-V is not submitted within the time prescribed in sub-paragraph (2), the date of submitting Form ITR-V shall be deemed to be the date of filing the return.

4. **Revised Return of Income.-** An eligible person as mentioned in paragraph (3) may furnish a revised return of income under sub-section (5) of section 139 of the Act or of fringe benefits under sub-section (4) of section 115WD of the Act for an assessment year under this Scheme if he has furnished a return of income or return of fringe benefits for that assessment year under the scheme.

5. **Qualifications of an e-Return Intermediary.-** (1) An e-Return Intermediary shall have the following qualifications, namely:-

- (a) it must be a public sector company as defined in clause (36A) of section 2 of the Act or any other company in which public are substantially interested within the meaning of clause (18) of section 2 of the Act; or
- (b) a firm of Chartered Accountants or Advocates, if it has been allotted a permanent account number; or
- (c) a Chartered Accountant or an Advocate, if he has been allotted a permanent account number; or
- (d) a Drawing or Disbursing Officer (DDO) of a Government Department.

(2) The e-intermediary should have at least class II digital signature certificate from any of the Certifying authorities authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying authorities.

(3) The e-intermediary should have in place security procedure to the satisfaction of e-Return Administrator to ensure that confidentiality of the assessee's information is properly secured.

(4) The e-intermediary should have necessary archival, retrieval and, security policy for the e>Returns which would be filed through him, as decided by e-Return Administrator from time to time.

(5) The e-intermediary or its Principal Officer, must not have been convicted for any professional misconduct, fraud, embezzlement or any criminal offence by any court of law or by any professional body, as the case may be.

6. Authorisation of e-Return Intermediary.

(1) A person qualifying to be appointed as an e-intermediary shall apply to the Registrar, along with such application fee, as may be decided by e-Return Administrator, from time to time.

(2) Upon receipt of the application, the Registrar shall verify that the application is complete and duly supported by necessary documents.

(3) In case of any defect in the application, the Registrar shall intimate the same to the applicant for removing the defects within the period specified in such intimation.

(4) Applications not satisfying the qualifications specified in paragraph 5 shall not be processed further.

(5) In case of a valid application the Registrar shall carry out due diligence of the applicant.

(6) The Registrar shall transmit the application and the 'due diligence' report online to the e-Return Administrator and thereafter the e-Return Administrator may issue an appointment order along with the e-Return Intermediary Identification Number (ERIIN) and password to act as an e-Return intermediary.

(7) The appointment of the e- intermediary shall be valid for a period of two years and may be extended for a further period of two years.

(8) The Registrar, including his employees, agents, franchisees, etc., shall maintain confidentiality of any information that comes to their possession during the course of implementation of this scheme and shall not part with any such information except with the prior permission of the e-Return Administrator.

7. Refund of security deposit to an e-Return Intermediary under the earlier scheme. -

Where a person has been appointed as an e-Return Intermediary under the "Electronic Furnishing of Income Scheme, 2004", the security deposit made by him shall be refunded to him by the e-Return Administrator within the time decided by the e-Administrator.

8. Procedure to be followed by the eligible person.- An eligible person opting to furnish his return of income under this scheme shall –

- (i) ensure that his return of income or fringe benefits falls under this scheme;
- (ii) approach and give his consent to any one of the e-Return Intermediaries to act as his agent for the purpose of furnishing his e-Return for the relevant assessment year.

9. Procedure to be followed by e-Return Intermediary.-(1) An e-Return Intermediary shall receive the paper return of income, duly verified by the eligible person or shall prepare the return of income on the basis of the documents furnished by the eligible person, as the case may be.

(2) The intermediary shall upload the completed return of income, after validation of permanent account number, in the format specified by the e-Return Administrator, using his e-Return Intermediary Identification Number (ERIIN).

(3) The uploaded returns shall be accepted after necessary validations. In respect of each accepted e-return, a duly filled Form ITR-V shall be generated by the system as a provisional receipt which shall be transmitted to the intermediary.

- (4) The intermediary shall deliver the acknowledgement receipt of the Form ITR-V to the concerned eligible person if the Form ITR-V is collected by him for submission to the Income-tax Department.
- (5) The date of issue of the provisional receipt shall be deemed to be the date of filing of return of income if the Form ITR-V has been filed with the Assessing Officer within fifteen days from the date of issue of the provisional receipt. If the Form ITR-V is filed after fifteen days from the date of uploading the data then the date of filing the Form ITR-V will be the date of filing the return of income.
- 10. Processing of e-Return. -** (1) The e-Return shall be processed on priority basis.
- (2) The refund, if any, due to the assessee shall be either credited by the assessing officer directly to his bank account, using the Electronic Clearing Services of the Reserve Bank of India or be directly sent to the assessee.
- 11. Functions and responsibilities of e-intermediary.-** The e-Return Intermediary shall -
- (a) ensure that the assessee is an eligible person under this scheme;
 - (b) ensure that the assessee has quoted a correct and valid permanent account number;
 - (c) ensure that the particulars of advance tax, self assessment tax and tax deducted at source are in accordance with the documents enclosed;
 - (d) ensure that the paper return of income has been properly filled in and duly verified by the assessee, and the enclosures required to be filed with the return of income are enclosed;
 - (e) ensure accuracy of the data entry while transcribing the return of income and during its transmission;
 - (f) ensure that the electronic portion of the return of income is transmitted on or before the due date for filing the return of income;
 - (g) ensure that the paper return Form-ITR-V is filed with the assessing officer having jurisdiction over the concerned assessee;

- (h) retain for a period of one year from the end of the relevant assessment year the electronic data of the return of income and the information relating to the provisional receipts issued in respect of the returns filed through it;
- (i) provide to the assessee a paper copy of the e-return submitted by e-intermediary and the acknowledgement receipt of Form ITR-V filed to the Assessing Officer;
- (j) maintain confidentiality of the information that comes to his possession during the course of implementation of this scheme and shall not part with any such information to anyone, except with the prior permission of the assessee or the assessing officer;
- (k) ensure that all his employees, agents, franchisees, etc., adhere to the provisions of this scheme;
- (l) promptly inform the Registrar of any change in the particulars given in the application filed by it for registration;
- (m) abide by the instructions issued by the e-Return Administrator, from time to time, for proper implementation of this scheme.

12. e-Return Administrator.- (1) The e-Return Administrator shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for the day to day administration of the scheme.

(2) The e-Return Administrator shall ensure compliance by the e-Return Intermediaries with the technical requirements of the scheme.

(3) The e-Return Administrator shall be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies for proper and secure implementation of this scheme.

[Notification No. 210/2007/F. No. 142/16/2007-TPL]
SAMBIT TRIPATHY, Under Secy.